

(II) Need to start rail service on Purna-Akola railway line in Central Railway

श्री संजय धोत्रे (अकोला): महोदय, मध्य रेलवे के पूर्ण अकोला रेल लाइन का गेज परिवर्तन का काम पूर्ण हुआ और पिछले 7 अप्रैल, 2008 को इंजन का ट्रायल रन भी किया गया, लेकिन अभी तक इस लाइन पर पैसेंजर तथा मालगाड़ियों का आवागमन शुरू नहीं हुआ। यह मार्ग नांदेड़ और सिकंदराबाद जाने वाला महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। नांदेड़ शहर में इस साल सिख धर्म की गुरुता गद्दी के 300 वर्ष पूर्ण होने के कारण देश-विदेश से इस समारोह में शामिल होने वास्ते बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। माननीय रेल मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस रेल लाइन का सुरक्षा निरीक्षण का काम तुरन्त किया जाये और मार्ग को यातायात के लिये खोल दिया जाये।

(III) Need to extend the time limit for implementation of Tsunami Rehabilitation Programme in Kerala

DR. K.S. MANOJ (Alleppey): The State of Kerala had suffered great devastation in the Tsunami that occurred on 26th December, 2004. The Government of India has sanctioned Rs. 1441.75 crores as rehabilitation package for relief and rehabilitation of the affected victims and rebuilding the infrastructure. The various works under Tsunami Rehabilitation Programme are progressing. Due to the complexity of the technical and administrative process involved in the implementation of the projects and the crisis in the construction industry on account of escalation of price of building materials etc. the progress of the programme is delayed and it would not be possible to finish it before 31st March 2009. So the time for implementation of the TRP may be extended to next two more years so that the entire works would be completed.

(iv) Need to safeguard the interests of small traders facing closure due to advent of Multi-National Companies in the retail sector

SHRI SANTASRI CHATTERJEE (Serampore): A serious situation has arisen due to indiscriminate setting up of malls in different parts of the countries by foreign multinationals in collaboration or tie up arrangement with Indian Corporate Houses. The articles they are selling in retail market have become a cause of concern for the small traders whose livelihood are exposed to serious jeopardy.

Before giving license to such traders, a law is required to regulate their business transactions so that the interests of the small traders are safeguarded.

(v) Need to open a Passport Facility Centre at Agra in Uttar Pradesh

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, सर्वविदित है कि आगरा विश्व का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और देश विदेश से ताजमहल एवं अन्य मुगलकालीन इमारतों को देखने लगभग 12 हजार पर्यटक प्रतिदिन आगरा आते हैं और यह उद्योग सरकार की आय के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है लेकिन अफसोस की बात है कि विदेश मंत्रालय द्वारा नए खुलने वाले 68 पासपोर्ट फैसिलिटी सेंटर में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं कानपुर जनपद का तो नाम है, परन्तु आगरा जनपद का नाम इस सूची में नहीं है।

आगरा में पासपोर्ट कार्यालय की मांग बरेली में रीजनल पासपोर्ट आफिस खुलने के समय से ही रही है, परन्तु क्षेत्रीय जनता की मांगों को दरकिनार करते हुए बरेली के बाद गाजियाबाद में रीजन पासपोर्ट आफिस खुला और अब एक बार फिर नीति निर्धारकों की अनदेखी से 68 ने पासपोर्ट फैसिलिटी सेंटरों में भी विदेश मंत्रालय द्वारा आगरा का नाम शामिल न करना अत्यधिक गैर-जिम्मेदाराना कदम लगता है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि 68 नए खुलने वाले पासपोर्ट फैसिलिटी सेंटर में एक पासपोर्ट कार्यालय आगरा में स्थापित हो।

MR. DEPUTY SPEAKER: Now I request Shri Baalu to move the Bill under item No. 31.

THE MINISTER OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI T.R. BAALU): Sir, may I request you to take up item Nos. 31 and 32 together?

MR. DEPUTY SPEAKER: Does the House agree to take up item Nos. 31 and 32 together?

SHRI K.S. RAO (Eluru): Yes, Sir, because the subject is the same for both the Bills.

MR. DEPUTY SPEAKER: So, the House agrees to take up both item Nos. 31 and 32 together.

SHRI B. MAHTAB (Cuttack): If both the Bills are to be taken together, the time allotted should not be the same. ...(*Interruptions*)